

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 206
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: 100-दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां

*206. श्री खगेन मुर्मु:
श्री तापिर गावः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार के 100-दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंत्रालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं:
- (ख) क्या जलवायु के अनुकूल और अधिक उपज देने वाले बीजों की कोई नई किस्म शुरू की गई है; और
- (ग) पीएम-किसान योजना के तहत त्रिपुरा सहित राज्य-वार कितने नए किसान जुड़े हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“100 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां” के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 206 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संदर्भ में विवरण।

- (क) सरकार के 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।
- (ख) जी हां, 100 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, 109 नई बीज किस्में, राष्ट्र को समर्पित की गई हैं, जो जलवायु अनुकूल और उच्च उपज जैसी विशेष विशेषताओं से युक्त हैं।
- (ग) त्रिपुरा सहित पीएम-किसान के अंतर्गत जोड़े गए नए किसानों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

100 दिवसीय कार्यक्रम की उपलब्धियां

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 2 सितंबर, 2024 को 2,817 करोड़ रुपये के बजट के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। फसलों, मौसम, पानी आदि के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली बनाने के लिए राज्यों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का समन्वय किया जा रहा है।
2. ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए “कृषि पैरा एक्सटेंशन वर्कर” के रूप में कृषि सखी प्रशिक्षण और प्रमाणन शुरू किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि के लिए पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कृषि सखियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 70,002 कृषि सखियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
3. एग्रीशोर – स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए सेबी पंजीकृत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में कृषि कोष को 750 करोड़ रुपये के लॉन्च किया गया, ताकि शुरुआती चरण के कृषि स्टार्ट-अप को इक्विटी और ऋण के रूप में पूंजी प्रदान की जा सके।
4. कैबिनेट ने पीएम कुसुम के साथ अभिसरण की सुविधा के लिए एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी; पात्र गतिविधियों के रूप में एकीकृत माध्यमिक प्रसंस्करण गतिविधियों को शामिल करना; व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियाँ (जैसे पॉलीहाउस, मशरूम की खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग आदि) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए पात्र हैं और एनएबी संरक्षण के तहत कवर किए गए एफपीओ के लिए ऋण गारंटी।
5. कृषि फसलों में कीट निगरानी, पहचान और प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) शुरू की गई।
6. कैबिनेट ने 9 क्लीन प्लांट प्रोग्राम की स्थापना के माध्यम से फल किसानों को प्रमाणित, रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए 1,767 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना के रूप में क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी दी।
7. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विभिन्न निवेश अवसरों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि निवेश पोर्टल शुरू किया गया।
8. विभिन्न कृषि स्टैकहोल्डर्स द्वारा निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली शुरू की गई। यह एक डिजिटल भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है जो उपग्रहों, मौसम केंद्रों, स्मार्ट फोन आदि से असंख्य डाटा बेस होस्ट करता है तथा ओपन-सोर्स टूल्स का उपयोग करके विश्लेषण का समर्थन करता है।
9. ई-कॉमर्स के लिए सक्षम बनाने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर 7,757 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल किया गया।
10. एफपीओ को व्यवसाय के लिए आवश्यक विभिन्न इनपुट लाइसेंस और वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंत तक, 4191 एफपीओ को बीज लाइसेंस, 3770 एफपीओ को

उर्वरक लाइसेंस, 3220 एफपीओ को कीटनाशक लाइसेंस, 1997 एफपीओ को एपीएमसी लाइसेंस, 4367 एफपीओ का एफएसएसएआई पंजीकरण और 6023 एफपीओ को जीएसटीएन जारी किया गया।

11. सरकार ने आवश्यकता आधारित कदम भी उठाये हैं, जिसमें 100 दिन का कार्यक्रम भी शामिल है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। कृषि व्यापार नीति में हाल के कुछ बदलाव इस प्रकार हैं :

प्याज:

- न्यूनतम निर्यात मूल्य को पूरी तरह हटाने तथा निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% करने के हाल के निर्णय से निर्यात खुलने की उम्मीद है।

बासमती चावल:

- बासमती चावल के लिए 950 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने के स्वागत योग्य निर्णय से अब चावल किसानों को अपनी प्रमुख उपज के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी।

खाद्य तेल - पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी:

- कच्चे तेल (पाम, सोया और सूरजमुखी) पर प्रभावी आयात शुल्क को 5.5% से बढ़ाकर 27.5% और रिफाईंड तेल पर 13.75% से 35.75% तक बढ़ाने का हालिया ऐतिहासिक निर्णय किसानों के पक्ष में रहा है।

सरकार के 100 दिनों के दौरान पीएम-किसान योजना में शामिल नए किसान

#	राज्यों के नाम	किसानों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	339
2	आंध्र प्रदेश	51,975
3	अरुणाचल प्रदेश	607
4	असम	1,64,952
5	बिहार	25,099
6	छत्तीसगढ़	74,071
7	चंडीगढ़	1
8	दिल्ली	1 11
9	गोवा	110
10	गुजरात	1,30,772
11	हरियाणा	21,996
12	हिमाचल प्रदेश	22,838
१३	जम्मू और कश्मीर	10,028
14	झारखंड	1,07,038
15	कर्नाटक	31,037
16	केरल	60,473
17	लद्दाख	94
18	लक्षद्वीप	323
19	मध्य प्रदेश	8 8,036
20	महाराष्ट्र	3 8,805
21	मणिपुर	425
22	मेघालय	22,753
23	मिजोरम	1 3,434
24	नागालैंड	3, 831
25	ओडिशा	1,19,092
26	पुदुचेरी	22
27	पंजाब	1 8,254
28	राजस्थान	4,50,620
29	सिक्किम	5, 588
30	तमिलनाडु	20,816
३१	तेलंगाना	3,589
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	59
33	त्रिपुरा	8,110
34	उत्तर प्रदेश	12,14,915
35	उत्तराखंड	24,165
36	पश्चिम बंगाल	30,870
	कुल	27,65,248